International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
An International Quarterly bi-lingual Multidisciplinary Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal
ISSN :2581-9925, Impact Factor (Cosmos: 7.555 & I2OR: 5.105), Volume 08, No. 02(II), April- June, 2026, pp. 207-210

रीवा जिले में वनोपज संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन एवं व्यापारिक संरचना का अध्ययन

शिवानी सिंह[1*] | डॉ. मनीष कुमार शुक्ला[2]

[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)।
[2]प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह, महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)।

[*]Corresponding Author: pariharshivanisingh771@gmail.com

Citation: सिंह, शिवानी एवं शुक्ला, मनीष (2026). रीवा जिले में वनोपज संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन एवं व्यापारिक संरचना का अध्ययन. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 08(02(II)), 207–210. https://doi.org/10.62823/IJEMMASSS/8.2(II).9149

सार

रीवा जिला मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख वन–संपन्न क्षेत्र है, जहाँ वनोपज संसाधनों का आर्थिक एवं वाणिज्यिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य रीवा जिले में उपलब्ध वनोपज संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन तथा उनकी व्यापारिक संरचना का विश्लेषण करना है। वनोपज जैसे– तेंदूपत्ता, महुआ, आंवला, हर्रा एवं बहेरा न केवल स्थानीय समुदायों की आजीविका का आधार हैं, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि यदि वनोपज के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं संगठित विपणन तंत्र को सुदृढ़ किया जाए, तो इन संसाधनों से प्राप्त आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। अतः वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप एवं संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।

शब्दकोशः *वनोपज, आर्थिक मूल्यांकन, व्यापारिक संरचना, लघु वनोपज, मूल्य संवर्धन, रीवा जिला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था।*

प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील देश में प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक उपयोग विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। विशेष रूप से वन संसाधन न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, बल्कि ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों के जीवनयापन का प्रमुख साधन भी हैं। मध्यप्रदेश, जो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, वनोपज संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। रीवा जिला विंध्य क्षेत्र में स्थित, विविध प्रकार की वनोपज संपदा से युक्त है। यहाँ के वनों में तेंदूपत्ता, महुआ, हर्रा, बहेरा, आंवला आदि प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक, औषधीय एवं खाद्य उत्पादों के रूप में किया जाता है। वनोपज संसाधनों का यह विविध स्वरूप क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परंपरागत रूप से वनोपज का उपयोग स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता था, किंतु वैश्वीकरण एवं बाजार विस्तार के परिणामस्वरूप इनका वाणिज्यिक महत्व बढ़ा है। वर्तमान समय में वनोपज का व्यापारिकरण

[*] *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

ग्रामीण विकास एवं आय सृजन का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। हालांकि वनोपज संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन एवं व्यापारिक संरचना में कई असंतुलन विद्यमान हैं। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव, मध्यस्थों की प्रमुख भूमिका, तथा संगठित विपणन तंत्र की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की अपर्याप्त सुविधाएँ भी आर्थिक लाभ को सीमित करती हैं। वर्तमान संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि वनोपज संसाधनों का वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाए। इससे न केवल संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावना बढ़ेगी, बल्कि व्यापारिक संरचना को भी अधिक संगठित एवं पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

अतः प्रस्तुत अध्ययन रीवा जिले में वनोपज संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन एवं व्यापारिक संरचना का विश्लेषण करते हुए, उनके वाणिज्यिक उपयोग की संभावनाओं एवं चुनौतियों का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है।

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य रीवा जिले में उपलब्ध वनोपज संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन एवं उनकी व्यापारिक संरचना का विश्लेषण करना है। वर्तमान आर्थिक परिवेश में वनोपज न केवल आजीविका का स्रोत है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि वनोपज संसाधनों का आर्थिक महत्व किस प्रकार निर्धारित होता है तथा उनकी व्यापारिक संरचना किस प्रकार कार्य करती है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित उद्देश्यों को शोध पत्र में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है –

- रीवा जिले में वनोपज संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन का अध्ययन करना।
- वनोपज के व्यापारिक ढाँचे एवं विपणन प्रणाली का विश्लेषण करना।
- वनोपज व्यापार में विद्यमान समस्याओं एवं सुधार की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन रीवा जिले के चयनित ग्रामीण एवं वन क्षेत्र से 300 उत्तरदाताओं के माध्यम से किया गया है। इसके लिए संरचित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया, जिससे वनोपज संग्रहण, आय स्तर, विपणन प्रक्रिया एवं व्यापारिक संरचना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकी। द्वितीयक आंकड़ों के लिए मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग, आर्थिक सर्वेक्षण, लघु वनोपज संघ की रिपोर्ट्स एवं विभिन्न शोध पत्रों का उपयोग किया गया है। इन आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से किया गया है। अध्ययन में सांख्यिकीय उपकरणों जैसे प्रतिशत विश्लेषण एवं सारणीकरण का उपयोग किया गया है, जिससे निष्कर्षों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के समन्वित उपयोग से अध्ययन को अधिक विश्वसनीय एवं व्यापक बनाया गया है।

विश्लेषण

रीवा जिले में वनोपज संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र ग्रामीण एवं आदिवासी समुदायों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तेंदूपत्ता, महुआ एवं अन्य लघु वनोपजों का संग्रहण न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करता है। व्यापारिक संरचना का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि वनोपज व्यापार मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में संचालित होता है, जिसमें मध्यस्थों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह संरचना संग्रहकर्ताओं को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने से वंचित करती है। वनोपज के मूल्य संवर्धन की संभावनाएँ अत्यधिक हैं,

किंतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण इनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। यदि स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाए, तो वनोपज का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। सरकारी योजनाओं एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यापारिक संरचना को अधिक संगठित एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल विपणन एवं ई–मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग भी वनोपज व्यापार को सुदृढ़ कर सकता है। इस प्रकार रीवा जिले में वनोपज व्यापारिक संरचना से संबंधित प्राथमिक समंकों के आधार पर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया गया है, जिसका विवरण सारणी क्रमांक 01 में दर्शाया गया है, जो इस प्रकार है–

सारणी 1: रीवा जिले में वनोपज व्यापारिक संरचना से संबंधित विवरण

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत (%)
1	प्रत्यक्ष विक्रेता (संग्रहकर्ता से बाजार)	60	20%
2	मध्यस्थों के माध्यम से विक्रय	120	40%
3	सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय	75	25%
4	प्रसंस्करण इकाइयों को विक्रय	45	15%
कुल योग		300	100%

स्रोतः क्षेत्रीय सर्वेक्षण, वर्ष 2024–2025

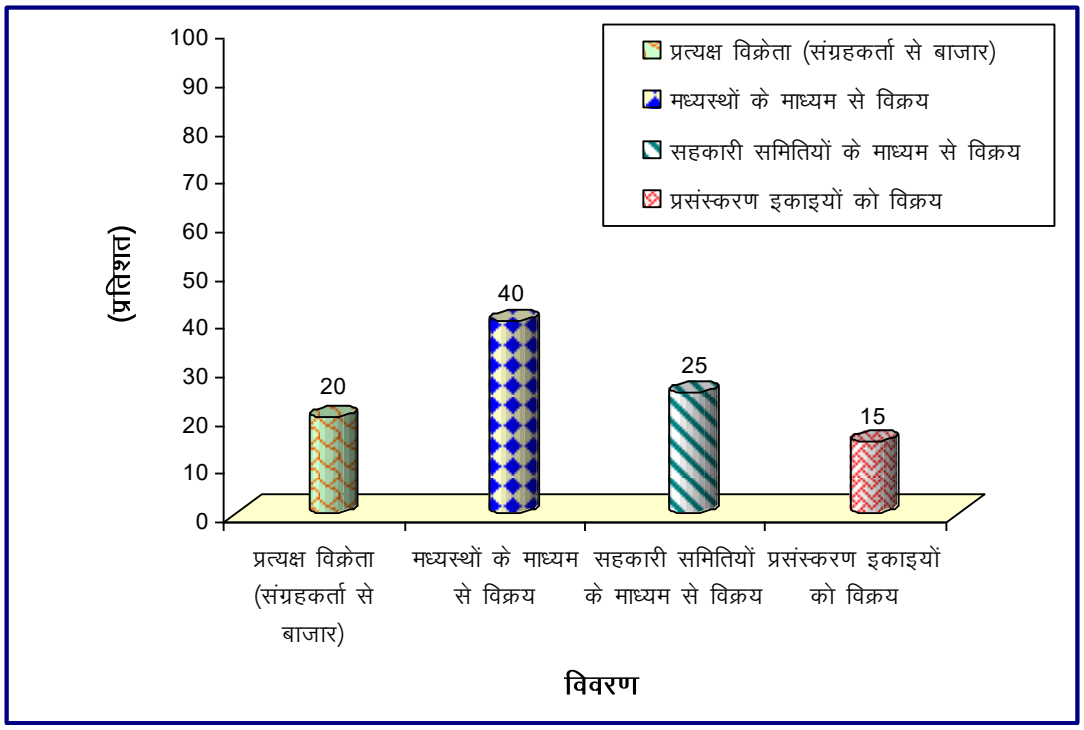

आरेख 1: रीवा जिले में वनोपज व्यापारिक संरचना से संबंधित विवरण

उपरोक्त सारणी एवं आरेख से यह स्पष्ट होता है कि वनोपज व्यापारिक संरचना में मध्यस्थों की भूमिका सर्वाधिक 40 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि संग्रहकर्ताओं का बाजार तक प्रत्यक्ष पहुंच सीमित है। केवल 20 प्रतिशत उत्तरदाता ही सीधे बाजार में विक्रय करते हैं, जबकि 25 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से विक्रय करते हैं। प्रसंस्करण इकाइयों को विक्रय करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 15 अपेक्षाकृत कम है, जो मूल्य संवर्धन की सीमित संभावनाओं को इंगित करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि वनोपज व्यापारिक संरचना को अधिक संगठित एवं सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

शोध की समस्याएँ एवं सुझाव

रीवा जिले में वनोपज संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन एवं व्यापारिक संरचना के अध्ययन के दौरान अनेक व्यावहारिक एवं संरचनात्मक समस्याएँ परिलक्षित होती हैं। प्रमुख समस्या यह है कि वनोपज का मूल्य निर्धारण व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया जाता, जिसके कारण संग्रहकर्ताओं को उनके उत्पाद का उचित आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। व्यापारिक संरचना में मध्यस्थों का वर्चस्व अधिक होने से लाभ का बड़ा हिस्सा उन्हीं तक सीमित रह जाता है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में उत्तरदाताओं की अनिश्चितता, अपूर्ण जानकारी तथा मौसमी प्रकृति के कारण डेटा की सटीकता प्रभावित होती है। तकनीकी ज्ञान, प्रसंस्करण सुविधाओं एवं भंडारण अवसंरचना का अभाव भी वाणिज्यिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है।

इन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक है कि वनोपज के लिए वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली विकसित की जाए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। सहकारी समितियों एवं सरकारी एजेंसियों के माध्यम से संगठित विपणन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, संग्रहकर्ताओं को प्रशिक्षण, प्रसंस्करण तकनीक एवं बाजार सूचना उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अधिक लाभ अर्जित कर सकें और वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके।

निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि रीवा जिले में वनोपज संसाधनों का आर्थिक महत्व अत्यंत व्यापक है, किंतु उनकी व्यापारिक संरचना में कई असंतुलन विद्यमान हैं। वनोपज का वाणिज्यिक उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की क्षमता रखता है, किंतु इसके लिए संगठित प्रयास आवश्यक हैं। मध्यस्थों की प्रमुख भूमिका, विपणन तंत्र की कमजोरी एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाएँ हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि वनोपज के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं संगठित विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इससे न केवल आय में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आर.के., वन अर्थशास्त्र, जयपुर, 2018.
2. सिंह, ए.के., थ्वतमेज म्बवदवउपबे पद प्दकपं, नई दिल्ली, 2019.
3. गुप्ता, एस.पी., लघु वनोपज एवं व्यापार, भोपाल, 2020.
4. वर्मा, एम.एल., छंजनतंस त्मेवनतबम म्बवदवउपबे, नई दिल्ली, 2021.
5. मध्यप्रदेश शासन, आर्थिक सर्वेक्षण, भोपाल, 2022.
6. लघु वनोपज संघ, वार्षिक प्रतिवेदन, 2023.
7. वन विभाग, मध्यप्रदेश, वार्षिक रिपोर्ट, 2024.

❑❑❑